

जल संकट

सरकार की जिम्मेदारी

जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पानी की बरबादी करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है, लेकिन सबल है कि क्या वह अपनी जिम्मेदारी तीक से निर्धारी है? दिल्ली में गर्मी खासकर बहुत अधिक है। इसका कारण 50 डिग्री सेल्सियस के आसापास तापमान तथा अक्सर चलने वाली लू है जिससे भयानक गर्मी पैदा होती है। इस सबके साथ नागरिक सेवाओं में कमी से समस्या और गंभीर हो जाती है। इससे नागरिकों को भारी पेशानी होती है। शहर में 'हाट आईलैंड' प्रभाव पैदा होता है जहाँ कंक्रीट गर्मी का शिकार होते हैं। जिससे बातावरण बढ़ते गर्म हो जाता है। खासकर परिचम में स्थित सुदूर ग्रामीण इलाके परिचम में राजस्थान के रेगिस्ट्रेशनों से आने वाली लू का शिकार होते हैं। इस मौसम में पानी की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है क्योंकि सलाई में भारी कमी आई है जिससे नागरिक अपनी व्याप तक ठीक से नहीं बुझा पाते हैं। एक अंडांशनर, कूलर और पंखे लाने के लिए बिजली की बिजली प्रिड या भारी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर बिजली कटौती होती है। गर्मी के साथ मिल कर वह श्वसन समस्याओं तथा अच्युत स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। दिल्ली को अंडे के समस्याओं हैं। हालांकि, आसमान से बसती आग के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, पर बिजली और पानी जैसे संसाधनों के बोहत प्रवर्षण से आग की गहरी दी जा सकती है। हर दिन दिल्ली सरकार हरियाणा पर उसके हिस्से का पानी जारी न करने का आरोप लगाती है, पर कोई समस्या का दीर्घकालीन समाधान नहीं चाहता है। इसके साथ ही दिल्ली के अंडे के दिल्ले से वह खासकर पूर्वी दिल्ली में समुचित हरित क्षेत्रों की कमी है जो छाया प्रदान करने तथा बातावरण ठंडा रखने के लिए जरूरी है। दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण शहर के प्रतिष्ठान चल ही रहा है। किनते सारे अनुभव हैं, किनती सारी अनुभूतियां हैं—मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसुस कर रहा हूँ।

बाकी 24 के इस चुनाव में, कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृतकाल के इस प्रथम समाजमा चुनाव में मैंने प्रसारण की अधियन 1857 के प्रथम स्वतन्त्र संग्राम की प्रेरणास्थली भेट से शुरू किया। माँ भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आश्विरी सभा पंजाब के होशियारुर में हुई। संत रविदास जी की उत्तर से अधिक जल भंडार नष्ट हो गए हैं। पिछले रिकार्डों से संकेत मिलते हैं कि दिल्ली में 1000 से अधिक जल भंडार थे जो पानी प्रदान करने के साथ ठंडक भी देते थे। बत्तमान जल संकट का सामान करने के लिए दिल्ली सरकार ने पानी की बरबादी के दोषी पर 2,000 रुपये जुर्मान का नियन्त्रण किया है। इस प्रकार दिल्ली सरकार जल-संकट की जिम्मेदारी नागरिकों पर धोखाना चाहती है। 20 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाली दिल्ली अभृतपूर्व जल-संकट का सामना कर रही है। बढ़ते तपामान से पानी का उपभोग बढ़ा है तथा पहले से ही दबाव का सामना कर रही जल सलाई व्यवस्था पर और दबाव बढ़ा है। नागरिक जल-संकट में भावधारों का सामना कर रहे हैं और केवल कुछ बढ़े ही पानी आता है। सरकार ने पानी की बरबादी वाली गतिविधियों की फैहान कारों की पायदो पर धूलाई, बागों में बहुत अधिक सिंचाई तथा पानी की टोंटियां खुली रखने के रूप में की है। हालांकि, सरकार का इरादा ठीक है, पर अंडे के तत्व इसकी प्रभावशीलता और व्यावहारिकता पर सबल उठाते हैं। सरकार दोषियों का पता कैसे लगाएं और पानी की बरबादी कोन परिभाषित करेगा? सरकार उत्तरी लोगों पर और कड़ाई करने जा रही है जो पहले ही बिजली और पानी के संकट के साथ ही भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं। इसके बजाय सरकार को पानी बरबाद करने वालों को चेतावनी देने के साथ जल संकट से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में टैक्टों की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अब केवल मौसम बदलने से ही राजधानी के नागरिकों को राहत मिलेगी।

